ड्रोन से दूरदराज तक पहुंचेगी डाक सेवा

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा- नई तकनीक से जन-जन तक मजबूत हो रही इंडिया पोस्ट की पहुंच

- मंडी से रेहड़धार तक ड्रोन से पहुंचाया तिरंगा
- हिमाचल में 110, असम में 40 ड्रोन रूट

नयी दिल्ली, 16 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय डाक ने तकनीक और राष्ट्रभक्ति का अनूठा संगम पेश करते हुए पहली बार ड्रोन के माध्यम से तिरंगे की डिलीवरी की।

केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश के मंडी हेड पोस्ट ऑफिस से रेहड़धार हेड पोस्ट ऑफिस तक ड्रोन के जरिए राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाया गया। रेहड़धार में भारतीय सेना के आर्मी मेडिकल कोर से सेवानिवृत्त मानद सूबेदार मेजर करतार सिंह ने तिरंगा प्राप्त किया। इस पहल को भारतीय डाक की बदलती तकनीकी कार्यप्रणाली और दूरस्थ क्षेत्रों तक तेज सेवाएं पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सिंधिया ने कहा कि भारतीय डाक का मूल मंत्र 'डाक सेवा, जन सेवा' है और विभाग इसी भावना के साथ आधुनिक तकनीक को अपनाकर देश के प्रत्येक नागरिक तक सेवाओं की पहुंच मजबूत कर रहा है।

> सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुआ 'हर घर तिरंगा' अभियान केवल सरकारी कार्यालयों या सार्वजनिक इमारतों तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य तिरंगे को प्रत्येक घर और प्रत्येक नागरिक के दिल में स्थापित करना है। भारतीय डाक इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए अपने व्यापक नेटवर्क और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रोन डिलीवरी के माध्यम से उन दूरस्थ और दुर्गम इलाकों तक भी डाक सेवाएं पहुंचाना आसान होगा.

नॉमिनी की जानकारी समय पर अपडेट करें

- बैंक खाते और निवेश में जांचें नॉमिनी का नाम
- शादी के बाद ईपीएफ नॉमिनेशन करें अपडेट

नई दिल्ली, 16 अगस्त बैंक खाता खोलते समय, नौकरी शुरू करते हुए, बीमा पॉलिसी लेते समय या किसी निवेश योजना में पैसा लगाते समय नॉमिनी का नाम दर्ज करना आम प्रक्रिया है।

हालांकि, ज्यादातर लोग एक बार नॉमिनी का नाम दर्ज कराने के बाद लंबे समय तक उसकी समीक्षा नहीं करते। जबकि समय के साथ परिवार और व्यक्तिगत परिस्थितियां बदलती रहती हैं। शादी, तलाक, बच्चे का जन्म या गोद लेना और नॉमिनी की मृत्यु जैसी स्थितियों में वित्तीय खातों और निवेश से जुड़े नॉमिनी रिकॉर्ड को अपडेट करना जरूरी हो जाता है। समय पर जानकारी अपडेट नहीं होने पर भविष्य में परिवार के सदस्यों को रकम पर दावा करने या उसे हासिल करने की प्रक्रिया में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

शादी के बाद व्यक्ति की पारिवारिक और वित्तीय स्थिति में बड़ा बदलाव आता है। यदि नौकरी शुरू करते समय किसी व्यक्ति ने अपने माता-पिता को नॉमिनी बनाया था और शादी के बाद वह अपने जीवनसाथी या बच्चों को नॉमिनी बनाना चाहता है, तो संबंधित रिकॉर्ड में आवश्यक बदलाव करना चाहिए।

अगस्त में एफपीआई निवेश 15,691 करोड़ बढ़ा

16621 करोड़ रुपये का इक्विटी में निवेश

40031 करोड़ रुपए एफपीआई ने जुलाई में लगाए थे

मुंबई, 16 अगर्स्त वदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) का भारतीय पूंजी बाजार पर भरोसा अगस्त में भी कायम रहा। अगस्त के पहले दो सप्ताह में एफपीआई ने भारतीय पूंजी बाजार में 15,691 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया है।

केंद्रीय डिपॉजिटरी सेवा के आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान विदेशी निवेशकों ने सबसे अधिक खरीदारी इक्विटी में की। अगस्त में अब तक इक्विटी में एफपीआई का शुद्ध निवेश 16,621 करोड़ रुपये रहा। हालांकि, डेट और हाइब्रिड खंड में विदेशी निवेशक शुद्ध बिकवाल रहे। म्यूचुअल फंड में उनका निवेश सकारात्मक रहा। आंकड़ों के अनुसार, एफपीआई ने अगस्त में हाइब्रिड खंड से 649 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की, जबकि डेट से 341 करोड़ रुपये निकाले। दूसरी ओर, म्यूचुअल फंड में उन्होंने 60 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया। बाजार में शुद्ध निवेश का अर्थ किसी अवधि में लगाए गए कुल धन और निकाले गए धन के बीच का अंतर होता है। अगस्त में एफपीआई का निवेश लगातार तीसरे महीने सकारात्मक रहा है। इससे पहले जुलाई में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में 40,031 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था। जून में भी एफपीआई 4,669 करोड़ रुपये के शुद्ध खरीदार रहे थे। लगातार तीन महीनों से विदेशी निवेशकों की खरीदारी से भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पूंजी के लौटने का संकेत मिल रहा है। हालांकि, पूरे कैलेंडर वर्ष की तस्वीर अभी भी अलग है।

> जनवरी से अब तक एफपीआई ने भारतीय पूंजी बाजार से कुल 1,57,150 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की है। ऐसे में जून, जुलाई और अगस्त में हुई खरीदारी के बावजूद वर्ष की शुरुआत से विदेशी निवेश का संतुलन नकारात्मक बना हुआ है। एफपीआई की हालिया खरीदारी से भारतीय शेयर बाजार को समर्थन मिल सकता है। इक्विटी में लगातार बढ़ता निवेश विदेशी निवेशकों के बीच भारतीय कंपनियों और घरेलू बाजार की संभावनाओं को लेकर सकारात्मक रुख का संकेत माना जा रहा है। हालांकि, आगे वैश्विक बाजारों की स्थिति, ब्याज दरों, कच्चे तेल की कीमतों और रुपये की चाल का असर विदेशी निवेश के रुख पर पड़ सकता है।

100 में बिका टाटा स्टील का फुटबॉल क्लब

- पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी बनी नई मालिक
- आईएसएल लाइसेंस और खिलाड़ी भी ट्रांसफर

नई दिल्ली, 16 अगस्त। टाटा समूह से जुड़ी कंपनी टाटा स्टील ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जमशेदपुर फुटबॉल एंड स्पोर्टिंग प्राइवेट लिमिटेड की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी महज 100 के मामूली प्रतिफल पर चर्चिल ब्रदर्स स्पोर्ट्स क्लब प्राइवेट लिमिटेड को बेचने का फैसला किया है।

सौदा कुछ पूर्व-शर्तों के पूरा होने पर 31 अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद है। चर्चिल ब्रदर्स के प्रमुख गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और उद्यमी चर्चिल अलेमाओ हैं, जबकि उनकी बेटी वालंका अलेमाओ क्लब की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

इस सौदे के साथ जमशेदपुर फुटबॉल एंड स्पोर्टिंग का इंडियन सुपर लीग लाइसेंस भी चर्चिल ब्रदर्स को हस्तांतरित होगा। इसके अलावा 12 खिलाड़ियों और दो कोचों के अनुबंध भी नए क्लब को सौंपे जाएंगे। यह बदलाव सितंबर 2026 से प्रभावी होने की बात कही गई है। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी के पास 4.08 करोड़ इक्विटी शेयर हैं, जिनकी अंकित कीमत 10 प्रति शेयर है, लेकिन पूरी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी का हस्तांतरण केवल 100 के मामूली प्रतिफल पर किया जा रहा है।

एलपीजी संकट से निपटने बढ़ेगा उत्पादन

नई दिल्ली, 16 अगस्त पश्चिम एशिया में संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते एलपीजी आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के बीच भारत सरकार ने घरेलू रसोई गैस की सुरक्षा मजबूत करने बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय ने रिफाइनरियों और तेल-गैस कंपनियों के लिए घरेलू एलपीजी उत्पादन के अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए हैं। 13 अगस्त के आदेश के तहत कंपनियों के लिए कुल 63,810 टन प्रतिदिन एलपीजी उत्पादन क्षमता निर्धारित की गई है। जरूरत पड़ने पर इन कंपनियों को तय लक्ष्य के अनुसार उत्पादन बढ़ाना होगा। इस व्यवस्था में रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर स्थित घरेलू बाजार के लिए संचालित रिफाइनरी को सबसे बड़ा उत्पादन लक्ष्य मिला है।

एसएमई लिस्टिंग के नियम होंगे आसान

सेबी 2 लाख की न्यूनतम निवेश सीमा हटाने समेत कई बदलावों पर कर रहा विचार

नई दिल्ली, 16 अगस्त छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना आने वाले समय में आसान हो सकता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) एसएमई मंच पर सूचीबद्ध होने वाली कंपनियों के लिए मौजूदा नियमों में कई बदलावों पर विचार कर रहा है।

प्रस्तावित सुधारों में पोस्ट-इश्यू पेड-अप कैपिटल की अधिकतम सीमा को 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करना और व्यक्तिगत निवेशकों के लिए 2 लाख रुपये की न्यूनतम आवेदन राशि में बदलाव शामिल है। इसके अलावा मार्केट मेकिंग और अंडरराइटिंग से जुड़े नियमों में भी राहत देने पर विचार किया जा रहा है।

प्रस्तावित बदलाव लागू होने पर अपेक्षाकृत बड़ी कंपनियों के लिए भी एसएमई आईपीओ के जरिए पूंजी बाजार में उतरने का रास्ता खुल सकता है। मौजूदा व्यवस्था में 25 करोड़ रुपये तक के पोस्ट-इश्यू पेड-अप कैपिटल वाली कंपनियां एसएमई मंच पर सूचीबद्ध हो सकती हैं। इसे बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये किए जाने पर करीब 5,000 करोड़ रुपये तक के बाजार मूल्य वाली कंपनियों के लिए एसएमई आईपीओ का विकल्प उपलब्ध हो सकता है।

वैश्विक कारकों पर निर्भर शेयर बाजार

मुंबई, 16 अगस्त बीते सप्ताह प्रमुख सूचकांकों में रही गिरावट के बाद आने वाले सप्ताह में घरेलू शेयर बाजारों की चाल मुख्य रूप से वैश्विक कारकों पर निर्भर करेगी।

निवेशकों की नजर पश्चिम एशिया संकट के साथ ही कच्चे तेल की कीमतों पर भी होगी। घरेलू स्तर पर नौ प्रमुख उद्योगों के जुलाई आंकड़े अगले सप्ताह जारी किये जाने हैं। शेयर बाजार की दिशा तय करने में इसका भी हाथ रहेगा। गत सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सोमवार और गुरुवार को मजबूत बंद हुआ

जबकि अन्य तीन दिन गिरावट देखी गयी। यह 489.92 अंक (0.62 प्रतिशत) की साप्ताहिक गिरावट में 78,009.25 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक सोमवार को छोड़कर अन्य चार दिन लाल निशान में बंद हुआ। सप्ताह के दौरान यह 204.65 अंक यानी 0.83 फीसदी गिरकर शुक्रवार को 24,366 अंक पर रहा। वृहत बाजार में मिश्रित रुख रहा। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.48 प्रतिशत चढ़ गया जबकि स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.65 प्रतिशत उतर गया। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 19 के शेयरों में साप्ताहिक गिरावट रही। टीसीएस का शेयर 3.86 प्रतिशत टूट गया। आईटीसी में 2.77 प्रतिशत, अल्ट्राटेक सीमेंट में 2.70, भारतीय स्टेट बैंक में 2.56, टाटा स्टील में 2.45, पावरग्रिड में 1.93, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.78, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1.77 और एक्सिस बैंक में 1.66 प्रतिशत की गिरावट रही।

1.30 करोड़ का पोर्टफोलियो

07 साल में पूंजी ने दिखाया जबरदस्त उछाल

10 लाख का कर्ज और भारी घाटा भी नहीं रोक सका

नई दिल्ली, 16 अगस्त शेयर बाजार में कम समय में बड़ा पैसा कमाने की चाह रखने वाले निवेशकों के लिए एक ट्रेडर की सात साल की यात्रा कई महत्वपूर्ण सबक देती है।

करीब 5 लाख रुपये की शुरुआती पूंजी से बाजार में कदम रखने वाले इस ट्रेडर ने उतार-चढ़ाव, भारी नुकसान और 10 लाख रुपये के कर्ज जैसे मुश्किल दौर का सामना करने के बाद करीब 1.30 करोड़ रुपये का पोर्टफोलियो तैयार किया। उनकी सफलता का आधार किसी खास शेयर की टिप या रातों-रात अमीर बनने का फार्मूला नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित ट्रेडिंग सिस्टम, बैकटेस्टिंग, जोखिम प्रबंधन और अनुशासन रहा। पिछले सात वर्षों में उनका वास्तविक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) करीब 48 प्रतिशत रहा ट्रेडर ने वर्ष 2018-19 के आसपास करीब 5 लाख रुपये से बाजार में शुरुआत की थी।

पंचा टीएम संथाली बुनाई को दिया नया जीवन

भोपाल, 16 अगस्त रामराज कॉटन ने पंचा टीएम नाम से एक नई हैंडलूम पेशकश लॉन्च की है, जिसमें ओडिशा के मयूरभंज की पारंपरिक संथाली बुनाई को आधुनिक धोती के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

पंचा के माध्यम से भारत की कम-ज्ञात बुनाई परंपराओं को पहचान दिलाने के अपने प्रयास को आगे बढ़ा रहा है, जिससे इस शिल्प को जीवित रखने वाली आदिवासी महिला बुनकरों को नई पहचान और आजीविका के अवसर मिल सकें। लॉन्च के अवसर पर रामराज कॉटन के संस्थापक एवं चेयरमैन, द कल्चरप्रेन्योर के. आर. नागराजन ने कहा, 'भारत की हैंडलूम विरासत बेहद विविधतापूर्ण है, लेकिन कई खूबसूरत बुनाई परंपराएँ आज भी केवल उन समुदायों तक ही सीमित हैं, जिन्होंने उन्हें जीवित रखा है। मयूरभंज की संथाली बुनाई ऐसी ही एक अनमोल विरासत है। हमारा मानना है कि इसकी मौलिकता बनाए रखते हुए इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचना चाहिए।

महिला बुनकरों की आजीविका को मजबूत करेगी

'पंचा' के माध्यम से हमने इस पारंपरिक बुनाई को धोती के रूप में नए स्वरूप में प्रस्तुत किया है, जिससे इस शिल्प के लिए एक नया अवसर तैयार हुआ है, साथ ही इससे जुड़ी कला और पहचान भी सुरक्षित बनी हुई है। हमें उम्मीद है कि यह पहल इस बुनाई के प्रति लोगों की सराहना बढ़ाएगी और उन महिला बुनकरों की आजीविका को मजबूत करेगी जिन्होंने इस परंपरा को आज तक जीवित रखा है। 'संथाली आदिवासी समुदाय की महिलाएँ परंपरागत रूप से इस विशिष्ट बुनाई से साड़ियाँ बनाती रही हैं, लेकिन संरक्षण में कमी, बदलती जीवनशैली और बाजार के सीमित अवसरों के कारण पिछले कई दशकों में यह बुनाई धीरे-धीरे अपनी पहचान खोती गई।

समाचार विशेष

कुशवाहा की पार्टी का विलय होगा क्या?

पटना. बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है। वे कुशवाहा समाज से आते हैं और नीतीश कुमार के बनाए लव कुश समीकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनको मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद भाजपा ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा और उनके बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए रखा है।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई बार की फटकार के बावजूद भाजपा ने उनको सरकार से नहीं हटाया। जब अदालत की नाराजगी बढ़ी तो भाजपा ने अपने एक सवर्ण एमएलसी का इस्तीफा करा कर दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य बनाया ताकि वे मंत्री बने रहें। अब सवाल है कि ऐसा क्या है, जिसकी वजह से भाजपा को उपेंद्र कुशवाहा की इतनी जरुरत महसूस हो रही है, जबकि मुख्यमंत्री उसी समाज के हैं। असल मे भाजपा चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय कर लें। पहले भी यह बात आई थी। तब उपेंद्र कुशवाहा ने सोच कर बताने की बात कही थी। तभी छह मई की रात को पटना के एक होटल में काफी देर तक मशक्कत चली थी। अंत में अमित शाह ने उनके बेटे के दूसरी बार शपथ लेने की मंजूरी दी थी। इसके बाद उनके राज्यसभा जाने के समय भी विलय का मुद्दा उठा। अब फिर उसकी चर्चा हो रही है।

दीपक प्रकाश क्या फिर होंगे एमएलसी

दीपक प्रकाश को जो एमएलसी की सीट मिली है उसका कार्यकाल आठ महीने का है। अगले साल मार्च में उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। फिर क्या उनको छह साल के लिए एमएलसी बनाया जाएगा? भाजपा के जानकार नेताओं का कहना है अगर उपेंद्र कुशवाहा विलय के लिए तैयार नहीं होते हैं तो मुश्किल होगी। भाजपा उनका विलय इसलिए चाहती है ताकि राजनीतिक रूप से जागरुक और जाति देख कर वोट करने वाला कुशवाहा समुदाय पूरी तरह से भाजपा के साथ ही रहे।

भाजपा नेता-कार्यकर्ताओं की नजर सरकार पर

निकाय-पंचायत चुनाव से पहले राजनीतिक नियुक्तियों की उम्मीद बढ़ी

जयपुर. राजस्थान में निकाय और पंचायती राज चुनाव की तैयारियां तेज होने के साथ ही लंबे समय से लंबित राजनीतिक नियुक्तियों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। कुछ ही समय में चुनाव आचार संहिता लागू होने की संभावित स्थिति के बीच भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में बोर्ड, आयोग और अकादमियों में नियुक्तियों को लेकर उम्मीद बढ़ गई है।

हाल में राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हुई नियुक्तियों के

बाद राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि सरकार अब अन्य खाली पदों को भरने की दिशा में भी कदम बढ़ा सकती है। भाजपा सरकार के करीब ढाई साल पूरे हो चुके हैं और पार्टी से जुड़े कई नेता लंबे समय से राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं।

भाजपा सरकार अब तक राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन अथॉरिटी, किसान आयोग, राज्य पशु कल्याण बोर्ड, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग, देवनारायण बोर्ड, श्री यादे माटी कला बोर्ड, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड, राज्य वित्त आयोग, आरपीएससी और आरबीएसई जैसी प्रमुख संस्थाओं में नियुक्तियां कर चुकी है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरुण चतुर्वेदी की नियुक्ति 1 अगस्त 2025 को हुई थी।

महिला आयोग की नियुक्ति भी अहम

महिला आयोग एक अर्ध-न्यायिक संस्था है, जिसे अधिकारियों को तलब करने, पुलिस रिपोर्ट मांगने, मामलों की जांच कराने और कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार है। ऐसे में लंबे समय से पद खाली होने को लेकर सरकार पर जल्द नियुक्तियां करने का दबाव है। पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष और कांग्रेस नेता रेहाना रियाज चिश्ती ने कहा कि उनका कार्यकाल खत्म हुए करीब 18 महीने हो चुके हैं.

गठबंधन की अटकलों पर ब्रेक!

रूपनगर. भाजपा प्रदेश विधानसभा की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अकाली दल से गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं। रूपनगर में सोमवार को भाजपा की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो ने साफ किया कि पार्टी की ओर से अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है।

ढिल्लों ने अकाली दल के सुखबीर बादल की प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात के बाद गठबंधन की संभावनाओं के संबंध में कहा कि प्रधानमंत्री सभी के हैं। सुखबीर बादल के भी हैं। सुखबीर पंजाब और अकाली दल के बड़े नेता हैं।

भाजपा ने 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के दिए संकेत

उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात में पंजाब के मुद्दों पर ही बात की होगी। जगतार सिंह हवारा को जेल से पैरोल दिलाने संबंधी कई राजनीतिक दलों की मांग पर भाजपा का पक्ष पूछे जाने पर ढिल्लो का कहना था कि उनकी पार्टी पंजाब के लोगों के साथ है और पार्टी हाईकमान का जो पक्ष होगा, वो पंजाब के हित में ही होगा।

सियासत कांग्रेस के सामने पहाड़ तो भाजपा के सामने तराई की चुनौती

दलबदलू नेताओं ने बदले चुनावी समीकरण

देहरादून. उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश की सियासत में दलबदल ने चुनावी समीकरणों को काफी बदल दिया है. कांग्रेस के कई पुराने और चुनाव लड़ चुके चेहरे भाजपा में जा चुके हैं, वहीं भाजपा के पूर्व विधायकों और स्थानीय प्रभाव वाले नेताओं ने भी कांग्रेस का रुख किया है. ऐसे में इस बार मुकाबला सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं रहने वाला, बल्कि पहाड़ बनाम तराई और पुराने संगठन बनाम नए चेहरों का समीकरण भी चुनावी नतीजों पर असर डाल सकता है.

दोनों पार्टियां अभी से संगठन और संभावित उम्मीदवारों को लेकर अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हैं.

कांग्रेस के लिए उत्तरकाशी जिले का समीकरण खास तौर पर बदल गया है. 2022 में कांग्रेस के टिकट पर पुरोला से मालचंद, यमुनोत्री से दीपक बिजल्वाण और गंगोत्री से विजयपाल सिंह सजवाण चुनाव मैदान में थे. अब ये तीनों नेता भाजपा के साथ हैं. इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस इन तीनों सीटों पर चुनाव से बाहर हो गई है, लेकिन पार्टी को स्थानीय स्तर पर नए चेहरे तलाशने और दूसरी पंक्ति के नेताओं को आगे बढ़ाने की चुनौती जरूर है. पहाड़ी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़, गांव-गांव का संपर्क और स्थानीय संगठन चुनाव में काफी मायने रखता है. ऐसे में कांग्रेस के लिए सिर्फ नया प्रत्याशी घोषित करना पर्याप्त नहीं होगा, उसे उसके पीछे पूरा संगठन भी खड़ा करना पड़ेगा. दलबदल के बाद गढ़वाल से लेकर कुमाऊं और मैदानी क्षेत्रों तक कई सीटों पर कांग्रेस की पुरानी चुनावी तस्वीर बदल गई है. टिहरी में धन सिंह नेगी, धनौल्टी में जोत सिंह बिष्ट, पौड़ी में नवल किशोर, लैंसडाउन में अनुकृति गुसाईं रावत, चौबट्टाखाल में केसर सिंह नेगी, यमकेश्वर में शैलेंद्र रावत और बदरीनाथ में राजेंद्र भंडारी जैसे नाम अब कांग्रेस के साथ नहीं हैं.

मैदानी और कुमाऊं क्षेत्र में खानपुर, रुड़की, कालाढूंगी, रुद्रपुर, भीमताल, बागेश्वर और धर्मपुर जैसी सीटों पर भी पुराने समीकरण बदले हैं. डोईवाला में वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट के निधन के बाद पार्टी के सामने अलग तरह की नेतृत्व चुनौती खड़ी हुई है. हालांकि इन सभी सीटों को कांग्रेस की कमजोर सीट मान लेना जल्दबाजी होगी. विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बदलने के साथ समीकरण भी बदलते हैं.

तराई बनाम पहाड़ का एंगल क्यों महत्वपूर्ण

2027 के चुनाव में तराई बनाम पहाड़ का राजनीतिक एंगल भी अहम हो सकता है. उत्तराखंड की पहाड़ी सीटों पर पलायन, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन और आपदा जैसे मुद्दे प्रमुख रहते हैं, जबकि तराई और मैदानी क्षेत्रों में उद्योग, कृषि, जमीन, रोजगार, शहरी विकास और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों का असर अधिक दिखाई देता है. ऐसे में दोनों पार्टियों के लिए एक जैसी रणनीति पूरे प्रदेश में काम नहीं करेगी. कांग्रेस के सामने पहाड़ में पुराने चेहरों के जाने के बाद नई लीडरशिप तैयार करने की चुनौती है, जबकि तराई में राजकुमार ठुकराल जैसे अनुभवी नेताओं की मौजूदगी से वह भाजपा के पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों को चुनौती देने की कोशिश कर रही है.